मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दे कर कामप्रीहेंसिव इन्कम टैक्स अमेंडमेंट बिल लायेंगे।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल आया है उस का मैं और प्रिन्सिपल विरोध करता हूं, और इसलिये करता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो यह रूलिंग दी है कि इन्कम टैक्स वैल्थ टैक्स को डिडक्ट कर के लगाया जाय क्योंकि दो दफा एक आदमी पर टैक्स नहीं लगना चाहिये, यह बिल इस सिद्धान्त के खिलाफ जाता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The hon. Member may continue on Monday.

---

15 hrs.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

Sixteenth Report

SHRI J. MATHA GOWDER (Nilgiris) : I beg to move the following :

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th August, 1972".

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That this House do agree with the Sixteenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 9th August, 1972."

The motion was adopted.

15-01 hrs.

RESOLUTIONS *RE : PER - CAPITA* INCOME—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will resume consideration of the Resolution moved by shri Bibhuti Mishra urging upon the Government to fix the minimum limit of *pet capita* income. Shri Jharkande Rai was on his legs. He has taken 13 minutes. He must conclude now.

श्री झारखण्डे राय (घोसी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पिछली बार यह बता रहा था कि हिन्दुस्तान के कम आय और बहुत आय वाले लोगों में कितना अन्तर है। हमारे देश में 57 फीसदी ऐसे खेतिहर लोग हैं जो खेती करते हैं और जिन के पास दो एकड़ से भी कम खेत हैं। दूसरी ओर सारे देश में पांच प्रकार के बड़े-बड़े जमीन चोर हैं। जिन के पास हजारों एकड़ जमीन हैं। घनश्यामदास बिड़ला के पास 80 हजार एकड़ हैं, माहोली शकर मिल के पास 2800 एकड़ हैं, हिन्दुस्तान शकर मिल के पास 3300 एकड़, महाराजा पटियाला के पास 1500 एकड़ हैं, महारानी गायत्रीदेवी के पास 4000 एकड़ के बाग के फार्म हैं इसी प्रकार अन्य के पास भी उत्तर प्रदेश में नैनीताल की तराई के इलाके में 5,000 एकड़ से ऊपर के तीन फार्म, 1,000 से 5,000 एकड़ तक के 12 फार्म, 500 से 1,000 एकड़ तक के 250 फार्म और 100 से 500 एकड़ तक 1,000 फार्म हैं: करियप्पा और थिमैया जो हमारे यहां के कमान्डर इन चीफ रह चुके हैं, उन के पास मैसूर में 5,000-5,000 एकड़ के फार्म हैं। हिन्दुस्तान में खेती योग्य जमीन दुनिया के करीब-करीब सब देशों से ज्यादा है। जैसे हिन्देशिया में 29%, अमरीका में 14% और कनाडा में 14% ही जमीन कृषियोग्य है। ढाई करोड़ एकड़ जमीन हिन्दुस्तान के पुराने सामन्तों और भूस्वामियों के पास है। पिछले बीस वर्षों में 2 हजार करोड़ खेती की पैदावार बढ़ाने पर व्यय किया गया है ऐसी स्थिती में देहातों में कम आमदनी और अधिक आमदनी का अन्तर बढ़ता जा रहा है। जमींदारी मुआवजा के रूप में केवल 1961 तक 164 करोड़ मुआवजा दे कर इस अन्तर को और बढ़ा दिया गया है। तीसरी योजना में अरबों रुपया खर्च कर के भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि नहीं हुई। चौथी योजना के बाद भी केवल नाम मात्र की बढ़ोतरी हुई है।

[श्री झारखंडे राय]

देश के देहातों में लाखों खेत मजदूर हैं जिन की आमदनी एक आने सें चार आने रोज तक है। देश में 15 करोड़ से ले कर 20 करोड़ तक आदमी ऐसे हैं जिन की रोज की आमदनी—खेत मजदूरों की——दो आने से तीन आने या चार आने तक है, जिस पर वह गुजर बसर करते है। सरकारी आंकड़े भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हिन्दुस्तान में दो करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की प्रति दिन की आमदनी 20 पैसे हैं, चार करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की आय 25 पैसे प्रति दिन है, छः करोड़ लोग ऐसे हैं जिन की प्रति दिन को आमदनी 32 पैसे है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति की दैनिक आय 1 रु० होने में पचास साल लेंगे, जिस रफ्तार से हम लोग चल रहे हैं। इसीलिये मैं कहता हूं कि यहां धनी और गरीब का अन्तर बेहिसाब बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि श्री मिश्र का प्रस्ताव ऐसा है जिस को इस सदन को सर्वसम्पति से स्वीकार करना चाहिये। प्रत्येक दृष्टि से आप देखिये, यह अन्तर देहाती क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है। देहाती जीवन में 13 फीसदी आदमी ऐसे हैं जिन के पास 60 फीसदी देहात की पूंजी एकत्रित हो चली हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर के इस तरह के उपाय निकाले जायें जिन से गरीब और अमीर का अन्तर कम हो। हर व्यक्ति की न्यूनतम आय निर्धारित हो जाय और कम से कम उतनी निर्धारित हो जिस से उस के परिवार का भरण-पोषण हो सके।

राष्ट्र संघ की सर्वे को अगर हम देखें तो उस से स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देश में 45 फीसदी ऐसे लोग हैं जिन की आमदनी 10 से 20 रुपये मासिक तक है। 30 फीसदी ऐसे लोग हैं जिन की आय 20 से 30 रुपये तक है। 24 फीसदी ऐसे लोग हैं जिनकी आय 30 से 50 रु० है और केवल 1 फीसदी ऐसे लोग हैं जिन की आय 50 रु० है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस अन्तर को कम करने के लिये श्री मिश्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाय।

एक तरफ कम आय के यह दयनीय स्थिति आंकड़े हैं और दूसरी तरफ घनश्यामदास बिड़ला हैं, जिन की पूंजी हिन्दुस्तान के स्वतन्त्र होने के समय किसी सूत्र से भी 40 करोड़ रुपये से अधिक नहीं थी। वह 298 करोड़ हुई, फिर 375 करोड़ हुई और आज 627 करोड़ तक पहुंच चुकी है। शहर और देहात दोनों जगह अमीर और गरीब की खाई चौड़ी और गहरी होती जा रही है।

इसलिये मैं आखिर में अपील करूंगा कि इस समस्या के समाधान दो ही हैं। या तो वर्तमान समाज, समाज के नियामक और सरकार के कर्णधार इस का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर लें अन्यथा कोई इस देश को रक्तरंजित क्रान्ति से बचा नहीं सकता। दो ही समाधान हैं : या तो शांतिपूर्ण समाधान या फिर रक्तरंजित क्रान्ति, दो ही आल्टरनेटिव हैं। इसलियें मैं श्री मिश्र का समर्थन करते हुये आशा करता हूं कि सदन उस को सर्वसम्मत्ति से स्वीकार करेगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री मिश्र ने जो प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है उस के द्वारा उन्होंने चाहा है कि सरकार प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय की कोई सीमा निर्धारित करे। हम अपनी स्वतन्त्रता की पच्चीसवीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। यह ठीक है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से प्रभावित होने के कारण चाहे हमारी धूमधाम में कमी हो, लेकिन यह बात जरूर है कि हम ने इस मुद्दे को अपनी दृष्टि में नहीं रखा कि हमारे देश में आम व्यक्ति की जो आमदनी है वह बढ़नी चाहिये या नहीं और उस को बढ़ाने का हम को क्या उपाय करना चाहिये।

परसों ही मैने एक अतारांकित प्रश्न संख्या 1523 में पूछा था कि :

(क) भारत में निर्वाह स्तर से नीचे के स्तर पर गुजर करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन पंचवर्षीय योजनाओं में से प्रत्येक में ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई; और

(ग) ये व्यक्ति कितने वर्षों तक न्यूनतम निर्वाह स्तर प्राप्त कर सकेंगे?

इस का जवाब योजना मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री ने दिया था। मैं प्रश्न के पूरे उत्तर को पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उन्होंने उत्तर के भाग (ग) में बतलाया था कि:

(ग) उपलब्ध अनुमानों से यह प्रतीत होता है कि यदि बेरोजगारी तथा आय-वितरण की समस्याओं पर सीधे प्रहार किये बिना केवल विकास पर निर्भर रहा जाय तो हो सकता है कि समाज के गरीबतम वर्गों को न्यूनतम उपभोग स्तरों तक पहुंचने में 30 से 50 वर्ष और लग जायें।

यह तो हमारी आर्थिक स्थिति है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो सरकार की अर्थ-नीति है या आर्थिक कार्यक्रम हैं, उन की सब से बड़ी असफलता है, और वह इस बात को सिद्ध करता है, और सरकार ने स्वयम् स्वीकार किया है कि हम न्यूनतम उपभोग की जो आवश्यकतायें हो सकती हैं किसी व्यक्ति की, उन को देने में पचास वर्ष और लगायेंगे । इसलिये हमारे इस सारे के सारे विचार में परिवर्तन की आवश्कता है।

जैसा अभी माननीय झारखन्डे राय बतला रहे थे किसी व्यक्ति की आय 20 पैसे है, किसी की 30 पैसे है और किसी की 40 पैसे है। और वह केवल एक दो व्यक्तियों की नहीं है, लाखों व्यक्ति 20, 30 और 40 पैसे पाते हैं। लेकिन हमारे समाजवाद की दुहाई देने वाले शायद यह भूल जाते हैं कि एअर-कंडिशन्ड बंगलों में रहने वालों और अच्छी बढ़िया एअर-कंडिशन्ड कारों में घूमने वालों की संख्या भी कम नहीं है। इतनी जो असमानता दोनों के अन्दर है उस को यदि हम मिटा नहीं पाये तो मैं समझता हूं कि समाज में इस विषमता को मिटाने के लिये होने वाली सामाजिक क्रान्ति को रोकने में सफल होना सन्देहास्पद है। वह तो हो कर ही रहेगी। यदि हम एक व्यक्ति को बार-बार कहते हैं कि तुम्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो जनता खड़ी होगी। जन आन्दोलन होगा। क्रान्ति होगी। समाज स्वयं परिवर्तन लायेगा....

श्री आर० डी० भंडारे (बम्बई मध्य): सामाजिक या राजनीतिक क्रान्ति?

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय: मैं सामाजिक क्रान्ति की बात कह रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वह सोच समझ कर बोल रहा हूं (**व्यवधान**) इस में चिन्ता की कोई बात नहीं है। क्रान्ति की आशा बहुत है। हमें यह सुनते हुये पचीस वर्ष हो गये कि बेकारी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी, बेकारों की संख्या कम होगी, लेकिन सरकारी आंकड़े बतलाते हैं कि समाज की जो स्थिति है, जिस को आप स्वयं स्वीकार करते हैं, भले ही आप मुंह से न कहें, उसमें बेरोजगारी की भीषण समस्या हमारे सामने हैं जब देश के उन नवयुवकों का चित्र हमारे सामने आता है जो न केवल अल्प शिक्षित या अर्ध-शिक्षित हैं बल्कि अच्छे शिक्षित हैं। ग्रेजुएट्स और पोस्ट-ग्रेजेएट्स को भी नौकरी नहीं मिलती है और चूंकि उनको नौकरी नहीं मिलती है, इस वास्ते वे आत्महत्या तक करने के लिये बाध्य हो जाते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कहां तक पहुंच पाई है यह भी देखने वाली बात है। इस प्रस्ताव का जहां तक सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की जो भावना है मूल रूप में बहुत सीधी-सादी है। कुछ आप तय तो करें, कुछ बताएं तो औसत आमदनी, न्यूनतम आय, न्यूनतम इन्कम आप क्या चाहते हैं तथा उसे कब तक दे पायेंगे। इसको ही आप तय नहीं कर पा रहे हैं। यही आप से नहीं हो पा रहा है। धारिया साहब ने जो उत्तर दिया था उस

[डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय]

में भी तय हो गया हो ऐसी बात नहीं थी। आप बतायें तो आखिर न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकता आप किस को समझते हैं। एक रुपये में एक व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, दो में कर सकता है अथवा तीन रुपये में कर सकता है, कुछ तो आप बतायें। देश की स्थिति को देखते हुये आप इस बात तक को नहीं कर पायें हैं। पच्चीस वर्ष में आप इतना सा काम भी नहीं कर पाये हैं। अब तो भीषण महंगाई कर चक्र चल रहा है। यदि एक बार आप यह तय नहीं कर पाते हैं कि प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय क्या हो तो पचास वर्ष की अवधि में भी आप उसके लिये इसकी व्यवस्था कर पायेंगे, इस में भी सन्देह है। ऐसा करने में आपको इससे भी अधिक समय लग सकता है। तब भले ही आप समाजवाद की कितनी ही घोषणायें करते जायें, समानता लाने के जितने भी नारे तक लगाते जायें, विषमता दूर करने की जितनी भी चर्चा करें, गरीबी हटाने के जितने भी नारे लगाते जायें, उनका कोई फायदा नहीं होगा। आप जनता को लगातार धोखा दे रहे हैं।

यह कहा गया है कि प्रति व्यक्ति आय कहीं पर बीस पैसे है और कहीं पर तीस पैसे। इस में तो वह एक जून का खाना तो क्या, उसकी जो क्षुधा है उसका कुछ भाग भी वह पूरा नहीं कर पाता है। तब वह परिवार का पालन-पोषण किस प्रकार करता होगा, यह सोचने की बात है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी ओर असंख्य लोग हैं जिन के पास विशाल सम्पत्ति है। मैं जो कह चुका हूं उसकी पुनरावृति करना चाहता हूँ। हमारे यहां समाजवाद और राष्ट्रीयकरण की लम्बी-लम्बी घोषणायें की जाती हैं, बड़े-बड़े नारे लगाये जाते हैं लेकिन उनका अब तक का परिणाम बेकारी और गरीबी की वृद्धि है। इसे दूर करने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जो प्रस्ताव लाया गया है पर कैपिटा अनुक्रम के बारे में, मूल रूप में वह सही है। सरकार को एक निश्चित आधार बना कर और एक सिद्धान्त को सामने रख कर आगे बढ़ना होगा। जो पिछड़े वर्ग हैं देश के उनके जीवन निर्वाह की जो सामान्य आवश्यकतायें हैं, उनकी पूर्ति न होना क्या निराशाजनक नहीं है। पचास वर्ष की अवधि नहीं बल्कि इस सारे काम को करने के लिये आपको पांच दस वर्ष की अवधि तय करनी होगी। यही सरकार के, देश के और हम सब के लिये लाभप्रद स्थिति रहेगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

SHRI BIREN DUTTA (Tripura West) : I support this Resolution. But at the outset, I feel pity for the Mover. He is an old member. He really feels like many Congress MPs, followers of the Congress here and outside. But this type of Resolution will not help in bringing about the desired effect. On the other hand, the fate of such a Resolution is that it creates some illusion which is persisting for the last 25 years in India. That is the most unfortunate part of it. Otherwise, he must have consulted the party and the Government which is running the administration for a long number of years and taken their approval or even the Government could have brought forward an official Resolution on these lines. The Government could have done it.

We are all practically feeling that the Resolution brought forward by the Mover is good and deserves consideration not only of the House but by the people outside. But this resolution will not be acceptable to the Government if it goes against those people who have practically all the wealth in their possession. The difficulty is this. The Government is manned by people who belong to the Mover's party, but the Government defends the interests of the capitalists, landlords and the exploiting classes not only of India but also of the international exploiters who are allowed to rob the Indian people. Under

these circumstances, everybody knows how severe and critical the economic situation is in India. We have heard the other day of people dying because of the severe drought situation in the country. It needs a radical reorientation of the total policies of the Government, and the people's democratic attitude should be adopted. Mr. Mishra had better push the party outside in the party meeting and then see that such a resolution is not opposed by the Government.

We are supporting, and everyone in this House will support this resolution but what is the use of supporting it. What is its fate going to be? One is sure that the Government will not accept it. Thereby, a serious doubt will crop up in the minds of the Congress fellows who sincerely believe that their party will and should do something good. When the people are bound to go against the Congress policies, then the Government will come down upon them with a heavy hand. The Congress fellows who are honest are just on lookers, bringing such resolutions and expressing their pious wishes but having no power to change the Government or the activities of the Government which supports only the landlords, capitalists and the exploiting classes of India.

That is why the time has come when I hope the Minister will hear the voice of reason inside the Congress and not the voice of the capitalists. Do not refuse this Bill ; accept this Bill and show that you are really meaning something which the Members of your party themselves are pressing on you through such a resolution which, I commend, should be accepted.

*SHRI E. R. KRISHNAN (Salem) : Hon. Mr. Deputy Speaker, Sir, on behalf of my party, the Dravida Munnetra Kazhagam, I would like to participate in the Debate on the Resolution of the hon. Member, Shri Bibhuti Mishra requesting the Government to fix a minimum limit of *per capita* income for the people of our country.

I am happy that the hon. Member belonging to the ruling party has brought such a welcome Resolution. In fact, he has come to realise that the *per capita* income even after 25 years' rule of his own party is so low that the Government should fix a minimum limit for the *per capita* income. I support wholeheartedly this Resolution.

In 1960-61 the *per capita* income in our country was Rs. 306. Keeping the prices in 1960-61 constant, the *per capita* income in 1969-70 has gone up to Rs. 329. At constant prices during the course of nine years, the *per capita* income has gone up by the paltry sum of Rs. 23. I am sure, Sir, you will not agree that the prices remained constant during all these 9 years. In fact, the prices during this period have gone up by 30%. Has the *per capita* income gone up in the same proportion? The answer is emphatic 'no'. It is really very unfortunate, that, when we are celebrating the Silver Jubilee of our Independence, the daily *per capita* income is not even 90 paise.

Let us take the wholesale price index during the last decade. If you keep 1960-61 as the base year and keep the wholesale price index at 100 points, in 1969 the all-India wholesale price index has gone up to 165 points. It is not that the essential commodities are made available at wholesale prices to the people. The retail prices of essential commodities must have gone up many times more than this. Has the *per capita* income gone up to the same extent?

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri E. R. Krishanan]

With a view to bringing down the prices and to raising the *per capita* income, Three Five Year Plans have been implemented and the Fourth Five Year Plan is in the process of implementation. It has also been accepted that the growth of public sector will lead to quick economic development and that is why Rs. 1996 crores, Rs. 4672 crores, 6300 crores and Rs. 15902 crores have been the play outlays in the First, Second, Third and Fourth Five Year Plans respectively. Even after such massive investment in the public sector, has it brought about any appreciable increase in the *per capita* income? Before the General Elections last year, the members and leaders belonging to the ruling party, the leaders of Opposition parties and so many others openly acknowledge on public platforms that all the investments in the public sector during the Fourth Five Year Plan have not helped to increase the *per copia* income and the benefits of these investments have gone to bloat the riches of 70 families in the country. The fact that the *per capita* income has not gone up shows that the benefits of planning have not gone to the poor people.

According to the statistics complied by the United Nations, the annual *per capita* consumption during 1967 in the U. S. A. was 3328 dollars ; in West Germany 1568 dollars ; in the U.K. 1626 dollars; in Japan 746 dollars. In Pakistan 113 dollars and in India 75 dollars. The annual *per capita* consumption is the lowest in India. West Germany and Japan were rared to the ground during the Second World War and the economic recovery of these two countries is really astounding. We got our independence more or less at the same time when the Second World War came to an end. I make bold to say that due to defective planning, due to lack of clarity in planning the economic development of the country, we are at the lowest rung of the ladder. The Prime Minister herself has accepted that all these years of planning have not gone to assist the common people in the country. The leaders of Old Congress Party have spoken about this.

nstead of planning for toppling whatever Opposition Party Governments are there in the country, the Government should start a re-thinking on the plan programmes. There should be a complete re-orientation of our plan efforts, which should raise the *per capita* income of our people. The priorities should be changed to achieve this objective. Inspite of the loudest call of *Garibi Hato*, everyone in this House will agree that throughout the country unemployment, famine, drought, starvation deaths, widespread malnutritiod etc. are the order of the day. I do not think the Government can deny the sufferings of the common people though Four Five Year Plans have been executed.

I would like to state here that the D. M. K. Government in Tamil Nadu has based all its activities on the sheet-anchor of spcialism. It is guided by the principle that there should not be economic concentration in a few hands and if the poor people are to derive any benefits from planning effortsthere should be economic decentralisation. The Government of Tamil Nadu has formulated meaningful plans for reducing the impact of unemployment and also for raising the *per capita* income, simultaneously bringing down the price spiral. Instead of conentrating on the methods for toppling such a progressive Government, the Central Government should try to formulate plans taking a cue from the efforts of Tamil Nadu Government so that the common people of the country are able to rise their standard of living. There is no use in making speeches and n writing articles about the total investments in all the Plans and about the

extent of external financial assistance, especially when we see every day in th newspapers reports about starvation deaths in the country. The widening gap between profession and practice must be bridged so that the efforts of the Government go to increase the *per capita*in come substantially. With these words I support the Resolution of Shri Bibhuti Mishra.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH) : Sir, I should have thought that this was a very imortant Resolution and would take some more time.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is non-controversial.

SHRI K. R. GANESH : I quite agree it is non-controversial but it is a very difficult resolution to implement in a large and complex country like India. It is not the spirit of the resolution which is in dispute or doubt. what is the strategy that the Government has to follow so that, step by step, we might be able to achieve the objective which the hon. Member has in mind?

I congratulate Shri Bibhuti Mishra who has moved this Resolution in this House. He is a person who in his own life symbolises the best that is in this country, all that Gandhiji had left for us ; he is the symbol of austerity and is an image of the largest section of people in this country. The fact that this Resolution has come from a veteran like Shri Bibhuti Mishra is indicative of the fact that we have, in this part of the House, apart from the legislative and constitutional provisions that have already been made, in our midst persons who are committed to this basic goal that the country has placed before itself. The objective of the hon. member is very laudable. In the directive principles of our Constitution and later in the concept of building a socialist society to which this Government and this Parliament are committed, we have made this commitment to our people that in the shortest possible time it should be possible for us to achieve a minimum degree of equality and provide the basic minimum needs to the largest section of our people. There is no dearth of legislative power. The directive principles themselves lays down these things and the concern that this House has from time to time expressed about these problems indicate that the goal of the nation has been set. Our great former Prime Minister, Jawaharlal Nehru, once siad :

> "That Service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man Mahatama Gandhi of our generation, has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over."

These are the accepted principles on which this old nation, now a new democractic State, has been founded. It is towards this objective that the political forces in the country are going.

We are entering the silver jubilee year of our independence. In the next few days, the country will re-dedicate itself to this noble task of eradication of all forms of exploitation and building a genuine real socialist society in which the vast masses of our people will become the masters. We have also discussed during the last few days that the 25th year has come at a time when we are faced with certain difficult problems like price rise, drought, etc. I do not have to go into details of these problems, because only yesterday this House

[Shri K. R. Ganesh]

extensively discussed them and the Finance Minister has indicated unequivocally the steps the Government intend to take. The only question I wish to pose is this : It is one thing to set a goal, it is another thing to achieve that goal by means of building a new economic order. We started from scratch. The British bled us. We could not produce even a small pin. There was no infrastructure at all. But what is the picture of India today? We have built vast industrial enterprises, basic industries, heavy industries and so on ; we have infused a new life in the agricultural sector. This is the infrastructure on which new wealth has to be created. This is the infrastructure that we have built up. With this we will have to create surplus wealth which will have to be distributed. Then only the disparity in income can be reduced.

An. hon. Member asked a question which I did not properly hear. But I know what he means. It took more than 40 years for a great country like the Soviet Union.

AN. HON. MEMBER : There is no unemployment there.

SHRI K. R. GANESH : I know it. For a great country like the Soviet Union which had a complete revolution and a centralised, regimented, organised political party to take control of the administration and work hard to build up that country right from scratch, it took nearly half a century. We must bear that in mind. We are the elected representatives of the people, responsible to the people. Most of us are elected by the poverty-stricken people and their poverty, as I said yesterday, is a shame to us. Therefore, we are naturally concerned about it. Even in that great country, Soviet union, there were certain economic inequalities at one time or the other because of which the capitalist press said that the Soviet Union has failed in its planning. I do believe those canards of the capitalist press.

The fact is that there are certain economic realities on which we have to build the super-structure. This government with the help of parliament and the socialist and democratic forces in this country had been trying to follow a strategy of planning development, of building heavy industries, of building the base of our agricultural economy. Every problem that is solved brings in another problem. We are a country with a huge population, 547 million according to the latest census. During the transitional period whenever we solve one problem, another problem comes.

Let us take the green revolution with all its connotations. Because of this increased food production we are now not depending on PL 480. That is why during the Bangladesh crisis we could stand up against the machinations and threats of the Seventy Fleet. Sir, probably you are under the impression that I am going deep into politics. The development and reconstruction of a nation is a total problem, which will have to be attacked totally.

AN. HON. MEMBER : Why is poverty increasing?

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : What about the position in China?

SHRI K. R. GANESH : I will not contest the hon. Member, with whom I politically disagree, that the Chinese have been able to solve some of their problems. I do not disagree with him. But see the conditions in which the Chinese revolution took place, a tremendous amount of mobilisation that China was able to make of its own people. Today we are in 1972. We need not only talk about China or Soviet Union. Even advanced capitalist countries

have tried to marginally solved the problem. It is a total strategy that we have to see. The Government is trying to put up a total strategy.

There is poverty. Nobody denies that. The Government itself is giving figurres to show that there is poverty in the country. I was deviated by a nice interruption that the hon. Member made about the green revolution. The green revolution did help us to produce more food. We have today 9.5 million tonnes of foodgrains. The Agriculture Minister has gone on record to say that the quantity of 9.5 million tonnes which we have is enough to feed India for another year and yet we will have 1.5 million tonnes left. It is a great achievement that we have made.

Yet the green revolution has produced another problem, the problem of tension, the problem of disparities, the problem of landless labour and that of rich farmers. The problem is there. The Parliament has been discussing this problem from time to time and it is our duty to find out a solution, a concensus, to see that the problem is solved.

We gave about Rs. 100 crores which may become Rs. 150 crores as food subsidy against the advice of the Agricultural Prices Commission, a high-powered, body, presided over the one of the finest economists in this country. We had to give Rs. 100 crores food subsidy so that the food prices are kept at a constant level. I am quite sure that there is a difference of opinion in the House as far as this is concerned. But there is one political reality which I, in all humility and honesty, want to place before this side of the House and that side of the House. When the Finance Minister with all his difficulties had provided only Rs. 75 crores for unemployment relief, for a crash programme, we had to provide Rs. 100 crores as food subsidy. All political parties, against the advice of the Agricultural Prices Commission, against the advice of some of the finest economists of the country, right from the C. P. M., said that the prices which the Agricultural Prices Commission has recommended should not be reduced. This is a political reality. We cannot get away from it. This is a basic reality. Unless this reality is changed, the priorities of changing the critical economic order in favour of vulnerable sections where money will have to be invested so that income equalisation can be achieved will not be possible.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Why are you retaining Kulaks?

SHRI K. R. GANESH : In all humility, I say, your party also supported it. I am putting a very honest question. At least, Comrade Indrajit Gupta should have stood up and said that this is wrong, that it is against all economic principles to invest Rs. 100 crores in the economy where 80 per cent of the people, the small farmers, after three months become consumers themselves. This is one reality.

Let us take another reality. Yesterday, Mr. Banerjee asked a question....

SHRI K. N. TIWARY (Bettaiah) : Do you mean to say that no remunerative price should be given?

SHRI K. R. GANESH : I am not saying that no remunerative price should be given. You want equalisation ; you want that certain basic amenities have got to be provided. 15 years of planning has touched the most articulate section of Indian society ; 15 years of planning has not yet touched 80 per cent of the people. The price-rise discussion, the food discussion and all the discussions that we have are all urban-or-

[Shri K. R. Ganesh]

iented discussions. To the person who is already living in a condition in which he is used to live, it is a very theoretical problem. The point that I was trying to drive at was this. 237.208 is the average 12-monthly cost of living index in June 1972. I have said this on the floor of this House. Government is committed to it. It will not be very very long when it becomes 238, and when it becomes 238, the Government will refer it to the Pay Commission and the Pay Commission will take a decision. In this Indian democracy, with this most vigilant Parliament, it will not be possible for any one to refuse another dose of interim relief unless the Pay Commission gives its recommendations earlier. Therefore, as a Finance Minister I am now faced with the problem. We are faced with the problem of injecting another Rs. 100 or Rs. 150 crores into the economy on a thing which is necessary because it saves erosion of income of a vulnerable section, of a better vulnerable section of society. You inject Rs. 150 crores now; you have already injected Rs. 100 crores for subsidy, for drought and all that, and you leave the basic problem of equalisation, the basic problem of the 80 per cent of the people who live in rural areas, who have not yet become articulate, who have not yet sent their representatives to this House, whether they come from this side of the House or that side of the House. There has been something wrong with the Indian political development. All of us who have come have come from particular class or group.

Let me take another problem. I am doing a little loud thinking. If in this Parliament we cannot tax pressure cooker, where is the resource ? We could not tax pressure cooker because there was a demand in Parliament ; it is a democracy and it had to be agreed to, it had to be withdrawn. The money involved might not have been much but it is the thinking that is there that is important.

In final analysis, I would say that the point that has been raised by the hon. Member, namely, full equalisation, is not possible in modern society. Basic amenities will have to be provided, basic minimum wages to the working class, whether they are organized and articulate or unorganized and most exploited—to all of them—will have to be povided, housing will have to be provided. All these things will have to be done. Over and above these, to create surplus, to create production, to create an industrial structure, you will have to provide incentives, you will have to see that certain surpluses remain in the hands of certain sections of the society who are in a position to invest. Govenment will have to create this surplus by the various strategies that the Government has been following. If we have failed to follow in a more determined manner, the Parliament can say that we have to follow in a more determined manner. But the aims et have been clear. The aims and objectives have been set clear by some of the finest leaders of the world who have become legendary today—Mahatama Gandhi and Jawaharlal Nehru. The Indian Constitution is a fine Constitution. It has laid down all the Directive Principles. Now, we are faced with the problem of creating wealth, creating the surplus to see that this particular problem is solved.

To create that surplus.... *(Interruptions)* I am speaking very seriously. I may not be able to appeal to you, but let me at least satisfy myself. To create that surplus we have created the infrastructure. The Heavy Engineering Corporation factory at Ranchi is one of the finest institution in the world, Now, all these infrastructures have been created. What is lacking—..*(Interruptions)* That is a very easy problem, the problem of getting

rid of Tatas, the problem of getting rid of Birlas, the problem of getting rid of Dalmias? 38% of who's investments are held by the Government financial institutions. This is one of the few governments in the world which have got all the financial institutions in its hands like LIC, etc. (*Interruptions*) There may be mistakes. Mistakes might be committed. I do not deny it. But the Parliament is vigilant enough to correct it. Sir, the infrastructure is there. What is lacking is the massive involvement of the people. Yesterday, I named a country. I will not name any country. But in small countries you can solve this problem...

SHRI E. R. KRISHNAN (Salem) : Then, better divide—(*Interruptions*).

SHRI K. R. GANESH : One of the most extreme forms of poverty and one of the most extreme forms of exploitation I have seen in the streets of a city in which I had my first political lesson, a city which I know, a city whose whole life I know. This is in answer to the hon. Member who said, 'Make the country small'. The country has to be big....

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharhapuram) : The hon. Minister as always been telling that the country is a very big country and the population is so high. He is always trying to escape under these two issues. I don't accept that....

SHRI K. R. GANESH : I am not yielding.

What I am saying is : what is necessary apart from...

SHRI INDRAJIT GUPTA : What are you saying about that city, the city of yours?

SHRI K. R. GANESH : If I say that, it will create another problem.

MR. DEPUTY SPEAKER : Anyway, let it be a city only.

SHRI K. R. GANESH : Now, the problem is : with the infrastructures that we have built up, with the heavy industries that we have built up, with the steel that we produce to-day, with the machine building industries that we have to-day, with the chemical industries we have to-day, with the help, with the faternal help of countries which do not want to exploit us—these are the assets—now the problem is to make these assets to work, to have the necessary men to work these assets and to involve these 40 million of our people in this task of national reconstruction. That is the basic political question. I put this question to Comrade Indrajit Gupta. That is the basic political question. The basic political question is the involvement of 40 million in this task. To-day we are 547 million. I said in that city on the 9th of August I addressed the Chhatra Parishad. It was a martyrs' day meeting. I went to that city. I know that city well. It was 22nd Novemver, 1945. When the Dalhousie firing took place I was there. (*Interruption*). Mr. Samar Mukherjee, if you do not know, please accept what I say, I was there when the firing took place. I went to that city. I told the *Chhatra Parishad* people, "We have to work." We have to work, I said, not to create Tatas, not to create Kulakhs, not to create black-money, but we have to work to end this. It will be a tremendous effort, requiring tremendous mobilisation of the entire people. My appeal to all sections of the House is....

MR. DEPUTY SPEAKER : Don't be sensitive..

SHRI K.R. GANESH : I am not sensitive. My appeal to all sections of the House is only this. (*Interruption*). Hon. Members of the opposition quote certain figures and statistics but they have not appreciated the problem in its true perspective. If China has solved, if Soviet Union has

[Shri K. R. Ganesh]

solved, if East European countries have solved, if Scandinavian countries have solved if even capitalist countries to an extent have solved, some of their problems, it has been with work, with involvement. It shall be the endeavour of this Government assisted by all hon. Members of the political parties to see that millions of people are involved. Sir, it is a very laudable Resolution moved by one of the finest Members. The Government agrees with the principle of the Resolution. Having agreed with that principle, I would only request him, Sir, that after he replies, he may withdraw the Resolution and create the necessary climate, the necessary idealism and the necessary determination which was the hallmark of Gandhiji, which he represents most, so that this nation can be built up and poverty can be tackled.

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष जी, माननीय वीरेन्द्र जी किस पार्टी के हैं मुझे पता नहीं। बात यह है कि उन की पार्टी में हिन्सात्मक बातें होती हैं। हमारी पार्टी में डिसिप्लिन है, हम पार्टी में रहते हैं, पार्टी ने हम को इतनी छूट दी है कि प्रस्ताव लायें, उस पर चर्चा हो। हमारे मंत्री जी ने प्रस्ताव की जो मंशा है उस को माना है, और मुझे आशा है कि सरकार उस मंशा के लिये कार्यवाही शुरू करेगी।

थोड़ासा सरकार के सम्बन्ध में मुझे कहना है। माननीय गणेश जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि हमारे यहां जो योग्य होता है उस में गणेश जी की सर्वप्रथम पूजा होती है, क्योंकि मैं कट्टर धार्मिक आदमी हूं, और ऐसे वैसे भी मैं उन की बड़ी इज्जत करता हूं, गणेश जी की पूजा करता हूं। लेकिन जो उन्होनें जवाब दिया है, क्योंकि उन के कैपिटलिस्ट प्रैगमैटिक होते हैं, उस खयाल से जवाब दिया है क्योंकि उन के आफिस में इम्पीरियल माइन्डेड ब्यूरोक्रेसी हैं। उन्होंने जो जवाब तैयार किया उसी के आधार पर। जवाब प्रेगमैटिक कैपिटलिस्ट के जैसे हैं, जवाब दिया। अगर अपने हृदय से जवाब देना होता तो मंत्री जी का दूसरा ही जवाब होता।

आप ने जो कहा है कि सोवियत यूनियन ने अपने मसलों को हल किया है, मेरा कहना है कि सोवियट यूनियन ने हल किया है। बल्कि जो उस की ब्यूरोक्रेसी है वह हावी है और वहां बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा तनख्वाह मिलती है, और तनख्वाह ज्यादा मिलने से सोवियट यूनियन में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। वहां एक बात है कि इंसेंटिव देते हैं कि इतना पैदा करो तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देंगे। इसलिये सोवियट यूनियन में बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है।

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : एक फ्रैंडली कन्ट्री के बारे में इस तरह का रिमार्क नहीं करना चाहिये, यह मेरा पोइंट आफ आर्डर है। माननीय सदस्य बिना फैक्ट जाने बोल रहे हैं, इसलिये आप इन को मना कीजिये।

MR. DEPUTY SPEAKER : That is not discourtesy.

श्री विभूति मिश्र : आप चाइना टुडे नाम की किताब पढ़ कर देखें तो आप को पता लग जायेगा, जो अभी हाल में निकली है।

दूसरी बात मैं बतलाना चाहता हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि जो पांचवीं फाइव इयर प्लैन है उस के हिसाब से हमारी गरीबी की बार्डरलाइन साढ़े 37 रुपया है। पांचवीं प्लैन में आप एक आदमी को साढ़े 37 रुपये देना चाहते हैं। आज आप राष्ट्रपति को 10 हजार रुपये देते हैं, यह कितने गुने ज्यादा होता है? आप मिनिस्टर को कितने गुना ज्यादा देना चाहते हैं। यह तो आप के हाथ की बात है। जब आप जमीन की सीलिंग बनाने जा रहे हैं, दस एकड़ से अट्ठारह, एकड़ रखने जा रहे हैं तथा पांचवीं प्लैन में हर आदमी को साढ़े 37 रुपये देना चाहते हैं तो मेरे पास उस का हिसाब है। यह रुपया देने के बाद आप के पास पांचवीं प्लैन के लिये बहुत कम रुपया बचेगा। देश की आबादी को देखते हुये आप डेवेलपमेंट पर बहुत कम खर्च कर पायेंगे

अप्रोच टु फाइव इयर प्लैन को देखते हुये न आप के पास सहूलियत है और न रुपया है। जब तक आप जो लोग सरकार में काम करते हैं, डाक्टर, प्रोफेसर क्लास 1, क्लास 2, मिनिस्टर, गवर्नर, राष्ट्रपति, सेठ, बड़े बड़े अहकाम हैं उन से पैसा नहीं लेंगे तब तक कोई भी प्लैन नहीं चलेगा और कोई उन्नति नहीं कर पायेंगे।

एक बात मैं बतलाना चाहता हूं। हमारे देश में जो इज्जत अहिंसात्मक रूप से गांधी जी की रही, पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही, जो इज्जत शास्त्री जी की रही या जो इज्जत इन्दिरा जी की है उतनी किसी भी डिमाक्रेटिक कंट्री में उस के नेताओं की नहीं है। चूंकि ये त्यागी हैं। सवाल यह है कि हम तनख्वाह में कमी करने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे इस को देख कर ताज्जुब होता है। इस का कारण यह है कि हमारे समाज में गांधी जी की आस्टेरिटी नहीं आई है, हमारे समाज में समाजवाद की भावना नहीं आई है। हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवाद चाहते हैं, लेकिन समाजवाद की भावना हमारी सरकार में नहीं आई है। इसीलिये इतनी डिस्पैरिटी है। अभी रेल गाड़ियों में इतने क्लास बने हुये हैं, और जगहों में क्लासेज बने हुये हैं। आप चाहते हैं डि क्लास करना, लेकिन कर नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी, और दूसरी जितनी पार्टियां हैं वह सब पूर्व जन्म से, जो स्वाधीनता की लड़ाई लड़ कर आई हैं, बुर्जुआ मेन्टेलिटी की हैं। जब तक यह बुर्जुआ मेन्टेलिटी रहेगी तब तक इस देश का कल्याण नहीं हो सकता।

जेफर्सन ने कहा है कि हर देश में दस-पन्द्रह वर्ष में क्रान्ति होनी चाहिये। लेकिन हमारे देश में क्रान्ति नहीं हुई। इस लिये डिस्पैरिटी बनी हुई है। आज क्रान्ति की जरूरत है, लेकिन क्रान्ति न आप से होती है न हम से होती है। हम तो बुड्ढे हो गये, आप जवान हो कर भी क्रान्ति नहीं करना चाहते।

एक बात और बतलाना चाहता हूं। आप चाइना की हालत को पढ़िये। वहां तनख्वाहों में बहुत कम फर्क है। वहां किसी को 100 येन मिलते हैं तो उस को 300 रुपये मान सकते हैं क्योंकि एक येन की कीमत तीन रुपये के लगभग की ही होती है। वे लोग जो गेहूं देते हैं वह 8 आने किलो पड़ता है। इस का कारण यह है कि वह मासेज को रिप्रेजेन्ट करते हैं और मासेज की बात करते हैं। वह सब कुछ मासेज से पूछते हैं। किन्तु हमारे यहां मासेज से कुछ नहीं पूछा जाता। हमारे यहां भी ब्यूरोक्रैसी है। कैबिनेट फैसले कर लेती है और उस फैसले को हमें मानना पड़ता है। यह पार्टी डिसिप्लिन है। इस लिये जब तक आप मास मनोवृति अपने दिल में नहीं लायेंगे—मास मनोवृति हमारे यहां नहीं है—तब तक हमारा काम नहीं चल सकता है। आप किसी भी बात को करने के पहले मास मनोवृति जानें।

अभी हाल ही में हम ने रेडियो में प्रधान मंत्री जी ने किसी अखबार वाले से कहा कि सरकार सीलिंग आन इंडिविजुअल इनकम के बारे में सोच रही है। अभी दो चार दिन पहले उन्होंने अखबार वाले को कहा है कि सरकार के दिमाग में, प्रधान मंत्री के दिमाग में यह है कि हर सैक्टर में सीलिंग लगाई जाये। राष्ट्रपति को आप दस हजार तनख्वाह देते हैं। वह भी कम होनी चाहिये। उस पर भी सीलिंग लगनी चाहिये। जब तक सब तरफ सीलिंग लगाई नहीं जाती है लोग चैन से नहीं बैठेंगे। देश का भला हो, इसलिये मैं यहां आया हूं। जिस दिन मुझे विश्वास हो जायेगा मेरी पार्टी कुछ नहीं करने वाली है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं इस पार्टी को छोड़ दूंगा। मैं हिन्दुस्तान को सही अर्थों में स्वाधीन देखने के लिये आया हूं, गरीबी मिटे, इस में सहायक होने के लिये आया हूं, पार्टी बंधन में इसी लिये हूं।

16 Hrs.

हमारे देश में एक सी भावना सब तरफ नहीं है। कारण यह है कि कोई रूस से बंधा हुआ है और कोई चीन से बंधा हुआ है। उनकी टेक हिन्दुस्तान में नहीं है। हमारी टेक हिन्दुस्तान

[श्री विभूति मिश्र]

में है और सब की टेक हिन्दुस्तान में होनी चाहिये चीन में क्या है। चीन वाले कोई भी काम करते हैं तो कहते हैं कि —फादरलैंड, समाजवाद और माम्रो, इन तीन के लिये हम करते हैं, इन तीन के लिये हम मेहनत करते हैं। मेनहर्ट ने वहां के लोगों से पूछा तो यही उन्होंने उनको जवाब दिया है। और आगे कहा कि जो हमारे समाज के दुश्मन हैं, जो विदेशी दुश्मन हैं, उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है इस लिये मैं चाहता हूं कि हम सब लोग भी चीन के लोगों जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी की लीडरशिप में विश्वास करें। और उनसे आप कहिये कि हिन्दुस्तान में जिस तरह की सीलिंग लगाता हो, लगाइये। आफिसर्स, मिनिस्टर्ज आदि सब पर सीलिंग हो। हर जगह सीलिंग हो लेकिन उसके साथ साथ मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड हिन्दुस्तान में आप दें। तभी इसके कुछ माने हो सकते हैं। यहां कुछ स्वतन्त्र पार्टी वाले हैं, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, कुछ खिचड़ी फरोश पार्टी वाले हैं। कितनी ही पार्टियां यहां हैं। इस वास्ते इन सब का एक मत होना मुश्किल है। हम लोग जो श्रीमती इंदिरा गांधी के पीछे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं, वे रेजोल्यूशन लाते हैं और रेजोल्यूशन ला कर सरकार पर दबाव डालना चाहते हैं कि वह उन कामों को करे।

गणेश जी के लिये मेरे मन में बड़ी इज्जत है। उनको मैं कहूंगा कि वह महात्मा गांधी के लेखों को पढ़ें। महात्मा गांधी यहां से वाइसराय से भेंट करने के लिये शिमला गये थे। लोगों ने कहा कि आप फर्स्ट क्लास में जायें, एयर कंडिशन्ड थर्ड क्लास में जायें लेकिन गांधी जी नहीं गये और तीसरे दर्जे में गये। हमारा लिविंग सिम्पल होना चाहिये तनख्वाहें हम को कम करनी चाहिये और जनता के मुकाबले में मान आना चाहिये। जमीन पर सीलिंग आप लगायें लेकिन उसके मुकाबले में आप अपनी जिन्दगी को भी ढालें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझिये कि आप गद्दी पर नहीं बैठे सकते हैं। तब यह पालिमेंट फैसला नहीं करेगी दुनिया में कहीं और—फैसला होगा। देश में तब क्रान्ति होगी। हमारी अपनी पार्टी में कुछ भाई हैं जो बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, हजारों हजार रुपये खर्च करते हैं, हजारों रुपया खर्च करना उनके लिये कोई मुश्किल बात नहीं है। इस पर भी रोक लगनी चाहिये। मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार जो इसके पीछे भावना है, उसको मानती है। वह तो ठीक है लेकिन उस भावना को आप कार्यान्वित करें और जल्दी से जल्दी करें। आप देखें कि देश में साठ लाख से ज्यादा लोग बेकार हैं। बी० ए०, एम० ए० तक बेकार फिर रहे हैं। वे लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। मेरा घर नेपाल के बोर्डर पर है। श्री के० एन० तिवारी जानते हैं। आये दिन वहां लोगों को गोली मार दी जाती है। दस बीस आदमी गोली से मारे जा चुके हैं। गरीबों और गरीबों के साथ और भी लोग मिल कर इस तरह के काम कर रहे हैं। एकसी सीलिंग तय होनी चाहिये और सब के लिये होनी चाहिये फिर चाहे कोई मिनिस्टर हो, लाट साहब हो, राष्ट्रपति हो। जब हम स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहे थे तो आश्रम के ढंग से हम रहते थे, एक ही पुआल पर सोते थे, एक ही ढंग का खाना खाते थे, एक तरह से प्रार्थना करते थे; जब जेल जाते थे तो किसी को सी क्लास मिल जाती थी और किसी को ए० क्लास। जिस को सी क्लास मिलता थी वह कहता था कि उसको ए० क्लास क्यों मिला। सेठ जमुना लाल बजाज सी क्लास में रहे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनको ए० क्लास चाहिये। चूंकि वह गांधी वादी थे। लेकिन अब जैसे ही कोई मिनिस्टर बन जाता है, वैसे ही उसका फर्निचर बदल जाता है, या एयर कंडिशनर बदल जाते हैं, सारी व्यवस्था बदल जाती है। जब वे केवल मेम्बर रहते हैं, तो उन की जो स्थिति होती है, फिर मिस्टिर बनने पर वह सब कुछ बदल जाता है। इस लिये मैं कहूंगा कि यद्यपि मंत्री महोदय मेरे प्रस्ताव की भावना को समझते हैं, लेकिन अगर उन्होंने देश में समाजवाद, समता और एकता लानी है और सरकार को चलाना है, तो वह इस को जल्दी कार्यान्वित

करें, वर्ना वे इस गद्दी पर बैठने वाले नहीं रहेंगे और न स्वतन्त्र पार्टी वाले बैठेंगे। वे धनी पार्टी के लोग हैं। जब सरकार मुनाफाखोरों की धरपकड़ कर रही है, तो जनसंघ के भाई कहते हैं कि उन्हें क्यों पकड़ा जा रहा है।

सरकार को पहले अपने खर्च में कमी करनी चाहिये। वह मिनिस्टरों, राष्ट्रपति और गवर्नरों आदि के खर्च और तनख्वाहों में कमी करे। वह उन की तनख्वाहों को जनता के समकक्ष लाये, वर्ना काम नहीं चलने वाला है। सरकार ने जो लैंड सीलिंग रखा है, उसी के समकक्ष सब का स्टैंडर्ड आफ लिविंग होना चाहिये, चाहे राष्ट्रपति हो या मिनिस्टर हो। हिन्दुस्तान में एक क्लास बन गई है, जो सारे देश पर राज्य करना चाहती है। मिनिस्टरों और धनी लोगों के बेटे विदेशों में जा कर पढ़ते हैं। इस प्रकार हिन्दुस्तान में सेठ-सेठानियों, राजा-रानियों और अफसरों की एक क्लास बन गई है, जो हम पर राज्य करना चाहती है और हम पर हावी होना चाहती है।

मैं एक डिसिप्लिन्ड पार्टीमैन हूं और मैं मरने तक पार्टी के खिलाफ काम नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इस बात से असंतोष है कि पच्चीस साल की आजादी के बाद भी सरकार ने हिन्दुस्तान की ग़रीबी को दूर करने के लिये अधिक मजबूत कदम नहीं उठाया है। इस का कारण यह है कि देश के ब्यूरोक्रेटिक अफसर कुछ नहीं करने देते हैं और मिनिस्टरों में उनको ओवर राइट करने की ताकत नहीं है।

हमारे यहां भावना की कमी है। अगर भावना होती तो हिन्दुस्तान की जनता ने हम को जो इतना विश्वास दिया था उसके द्वारा हम इस देश में एक हिंसक कल्चरल रेवोल्यूशन करते लेकिन हम ने आज तक ऐसा नहीं किया है। जिन अफसरों ने आजादी की लड़ाई में हम को जेल भिजवाया था आज वही गद्दियों पर बैठे हुये हैं। यदि सरकार को देश को चलाना है, तो वह इस प्रस्ताव की भावना को समझ कर देश में आर्थिक समता लायें। किसानों के लिये जो सीलिंग लगाई जा रही है, उसी के बराबर सबका जीवन-स्तर हो। किसानों के लड़के इन्टेली-जेंट होते हैं। माओ-त्से-तुंग ने किसानों के द्वारा चाइना में क्रान्ति की, फैक्टरी में काम करने वालों के द्वारा नहीं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, what do you want to do with the resolution?

श्री विभूति मिश्र : मैं इस को वापिस लेता हूं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Does he have the leave of the House to withdraw it?

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes.

The resolution was, by eave, withdrawn.

16.08 hrs.

RESOLUTION RE. PROBLEM OF ECONOMIC STAGNATION OF WEST BENGAL

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move :

> "This House demands that the Government should fulfil, without delay or dilution, its commitment and responsibilities towards solution of West-Bengal's urgent problems of economic stagnation."

16.08 hrs.

[SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*].

Sir, what are these commitments and responsibilities to which I refer? I do not want to take this hon. House through a narration of all the various assurances and promises which have been made on behalf of the Centre, both inside this House and outside, during the course of 1970, 1971 and right up to the genera elections of this year in the States. I think many hon. members will recall that on numerous occasions, beginning from the Prime Minister downwards to other Ministers, it has